भारत सरकार
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2316
उत्तर देने की तारीख 13 दिसंबर, 2021 (सोमवार)
22 अग्रहायण, 1943 (शक)

प्रश्न

बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के लिए धनराशि

†2316. श्री नव कुमार सरनीया:

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत असम राज्य सरकार को कितनी धनराशि जारी की गई है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद को कितनी धनराशि जारी की गई है;
(ग) विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा बीटीसी और असम राज्य सरकार को कितनी धनराशि जारी किए जाने की संभावना है और यह धनराशि कब तक जारी की जाएगी;
(घ) क्या सरकार को बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा कोई केन्द्र प्रायोजित स्कीम लागू नहीं की जा रही है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान असम सरकार को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों के तहत 1467.51 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय सीधे बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) को धन जारी नहीं करता है । हालांकि मंत्रालय ने असम राज्य सरकार को विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के लिए विशेष पैकेज के तहत धन उपलब्ध कराया। 750.00 करोड़ रुपये के इस पैकेज के तहत 749.63 करोड़ रुपये की 65 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनके एवज में पिछले तीन वर्षों के दौरान 3.85 करोड़ रुपये सहित 714.24 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। अब

तक 589.11 करोड़ रुपये की 54 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) जैसा कि ऊपर कहा गया है, मंत्रालय सीधे बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) को धन जारी नहीं करता है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण पत्र, भौतिक और वित्तीय प्रगति आदि सहित सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर स्वीकृत परियोजनाओं के लिए असम सरकार को धनराशि जारी की जाती है।

(घ) और (ङ) 27-01-2020 को भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूहों (एबीएसयू और एनडीएफबी गुटों) के बीच एक नए समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ ही, यह एमओएस अन्य बातों के साथ-साथ यह बताता है कि असम सरकार बीटीसी के अंतर्गत क्षेत्र के विशेष विकास के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 250.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित कर सकती है। इसके अलावा, भारत सरकार इसी अवधि के लिए प्रतिवर्ष 250.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का योगदान कर सकती है। अब तक, राज्य सरकार ने नवंबर, 2021 के महीने के दौरान बीटीसी के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत वित्तपोषण के लिए बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद द्वारा तैयार किए गए 265.00 करोड़ रुपये के 03 परियोजना प्रस्ताव भेज दिए हैं।

*****